राज्यपाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

स्वतंत्रता दिवस – 2022

राज्यपाल ने झण्डारोहण किया

जयपुर, 15 अगस्त। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने सोमवार को यहां राजभवन में स्वतंत्रता दिवस पर झण्डारोहण किया। बाद में उन्होंने पांचवी बटालियन आरएसी गारद की सलामी ली।

राज्यपाल श्री मिश्र ने राजभवन परिसर स्थित राजकीय विद्यालय के उच्च प्राप्तांक वाले छात्र–छात्राओं को पुरस्कार रुप में भारतीय संविधान पर लिखी पुस्तक भेंट की तथा मिठाई वितरण कर उनका उत्साह बढ़ाया ।

उन्होंने राजभवन स्थित औषधीय उद्यान में गूलर का पौधा भी लगाया। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला श्रीमती सत्यवती मिश्र, राज्यपाल के परिजन, प्रमुख विशेषाधिकारी श्री गोविन्द राम जायसवाल सहित राजभवन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

राज्यपाल श्री मिश्र का स्वाधीनता दिवस पर संदेश

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के संदेश का वाचन जिला स्तरीय समारोहों में करवाया गया।

राज्यपाल श्री मिश्र का स्वाधीनता दिवस पर संदेश अविकल रूप से प्रस्तुत है–

- आज हमारे देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम सब 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह ऐतिहासिक क्षण हम सबको गर्व की अनुभूति दे रहा है। इस गौरवशाली अवसर पर मैं सभी देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
- आजादी का यह महापर्व हमें याद दिलाता है उन स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों, महापुरूषों और महान नेताओं की जिनकी शहादत, त्याग, बलिदान और लंबे संघर्ष के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं।
- मैं स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली सभी ज्ञात–अज्ञात सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं और हमारे बीच मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों की स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं।
- आजादी के यह 75 वर्ष देश का वह स्वर्णिम काल है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे महान नेताओं के कुशल नेतृत्व, दूरगामी एवं तार्किक सोच और विजन के साथ ही आमजन के पुरूषार्थ से विकास यात्रा की लंबी दूरी तय की और सफलता के नए सोपान हासिल किए हैं।
- देशवासियों की 75 वर्ष की मेहनत, परिश्रम और जज्बे से तरक्की की जो इबारत हमने लिखी है, उसने दुनिया में हमारे देश को एक नई पहचान दी है। आधारभूत ढांचे से लेकर मानव संसाधन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीक, उद्योग, कृषि, सामरिक, पर्यटन, खेल, खनिज,

पेट्रोलियम सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपने उद्यम का लोहा मनवाते हुए हमने दुनिया में धाक कायम की है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जिसमें भारत का दखल नहीं है।

- प्यारे प्रदेशवासियों, राजस्थान भी इस विकास यात्रा में बड़ा भागीदार रहा है। इन 75 वर्षों में राजस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में शून्य से शिखर की यात्रा तय कर देश के समक्ष मिसाल पेश की है। अकाल–सूखा, भौगोलिक चुनौतियों, विषमताओं और संसाधनों की सीमितता के बावजूद राजस्थान ने साबित किया है कि अभावों के बीच सफलता का इतिहास किस तरह लिखा जाता है।
- जिस प्रदेश में आजादी के समय मात्र 13 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता हो, आज वह राज्य 23 हजार 465 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है। विशाल भू–भाग और अकाल से जूझने वाले इस राज्य में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना एक सपने की तरह था, लेकिन इस वीर धरा पर पैदा हुए जनप्रतिनिधियों के साहस और सूझबूझ का नतीजा है कि यह सपना अब साकार हो रहा है। प्रदेश की गांव–ढाणी और मरू जिलों में भी आज जल जीवन मिशन से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।
- प्रदेश के हर हिस्से में सड़कों का जाल बिछने के साथ ही नए–नए उद्योगों की स्थापना, आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण, गांव–ढाणी तक बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं, बेहतर सर्विस डिलीवरी, गुणवत्ता–युक्त शिक्षा, निवेश के लिए अनुकूल माहौल, सुदृढ़ कानून–व्यवस्था से राजस्थान अब बीमारू प्रदेश की छवि को पीछे छोड़ देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है। विकास के हर पैमाने पर राजस्थान नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
- संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन हमारी सरकार का मूलमंत्र रहा है। इस मूलमंत्र को निचले स्तर तक साकार करने की दिशा में राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
- 'पहला सुख निरोगी काया' की सोच के साथ हमारी सरकार ने निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए हरसंभव प्रयास किया है। राज्य सरकार ने राईट टू हेल्थ की दिशा में सकारात्मक भावना के साथ कदम बढ़ाए हैं।
- यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज की दृष्टि से हमारी सरकार ने ''मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा'' जैसी महत्त्वाकांक्षी योजना लागू की है। इस योजना से गरीब एवं जरुरतमंद वर्ग के साथ ही सभी प्रदेशवासी इलाज के भारी–भरकम खर्च की चिंता से मुक्त हो गए हैं।
- योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवार, सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 के अन्तर्गत पात्र परिवार, समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमान्त कृषक तथा कोविड–19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवारों का निःशुल्क बीमा किया गया है। साथ ही अन्य परिवार भी मात्र 850 रूपए वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना का लाभ ले रहे हैं।
- यह योजना लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। योजना में कॉकलियर इम्पलांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, बोन कैंसर जैसी जटिल बीमारियों का भी निशुल्क उपचार मिल रहा है। योजना में पहले 5 लाख रूपये तक निःशुल्क उपचार का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपये कर दिया गया है। अभी तक 18 लाख से अधिक मरीजों को करीब 2 हजार 203 करोड़ रुपये का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया गया है।
- हमारी सरकार ने सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी एवं इनडोर उपचार पूरी तरह निःशुल्क कर दिया है।मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए सीटी स्केन और एमआरआई जैसी महंगी जांचे भी निः ुल्क उपलब्ध हो रही हैं।
- राज्य सरकार के निर्णयों एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा नवाचारों के परिणाम स्वरूप विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांको में राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मातृ स्वास्थ्य में प्रगति वर्ष 2020–21 में जारी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात में 23 अंकों की

गिरावट आई है जो सभी बड़े राज्यों में सर्वाधिक है।इसी प्रकार पांच वर्ष तक शिशु मृत्युदर में 134 अंको की गिरावट आई है।

- आमजन को आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में 22 मंजिला आईपीडी टावर का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलोजी, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की जयपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइन्स की जोधपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ नियोनेटोलोजी एण्ड मेटरनिटी की कोटा में तथा इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एण्ड नियोनेटोलोजी की अजमेर में स्थापना की जा रही है। साथ ही जोधपुर में 130 करोड़ रूपये की लागत से क्षेत्रीय कैन्सर संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य की तरफ राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। सभी जिलों में राजकीय क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। गत वर्ष 7 नवीन नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ किये गये हैं। इस वर्ष 19 नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ किये जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में एमबीबीएस की सीटों में 58 प्रतिशत एवं पीजी सीटों में 48 प्रतिशत की अभिवृद्धि की गई है।
- आयुष चिकित्सा पद्धतियों की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए एक हजार आयुर्वेद औषधालयों को हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- गत साढ़े तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में 3 हजार 382 मेगावॉट की वृद्धि होने से कुल उत्पादन क्षमता 23 हजार 465 मेगावॉट हो गई है। इससे राज्य विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 9 हजार 545 मेगावॉट उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। राज्य में कुल 17 हजार 787 मेगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित हैं।
- प्रदेश में करीब 19 जिलों में किसानों को कृषि के लिए दिन में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। शेष 14 जिलों में अप्रैल, 2023 से दिन में विद्युत आपूर्ति किया जाना लक्षित है।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2 लाख 78 हजार 575 कृषि कनेक्शन एवं ग्रामीण क्षेत्र में 14 लाख 33 हजार घरेलू कनेक्शन जारी किये गये हैं। किसानों को बिजली के बिलों में लगभग 52 हजार करोड़ रूपए का अनुदान दिया गया है।
- किसानों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना' लागू की गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह एक हजार रूपये तक या प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रूपये तक अनुदान दिया जा रहा है।योजना के तहत लगभग 12 लाख 72 हजार किसानों को 1 हजार 134 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। इससे लगभग 7 लाख 21 हजार किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है।
- समस्त 119 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत की दृष्टि से 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसका लाभ करीब 18 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिला है। इसके साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को स्लेब के अनुसार छूट का लाभ मिल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में करीब 119 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को जून, 2022 तक 1 हजार 197 करोड़ रूपये की छूट दी गई है।
- प्रदेश के प्रत्येक शहर, कस्बे, गांव और ढाणी में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- जल जीवन मिशन के तहत अब तक प्रदेश के 38 हजार 168 गांवों में 9 हजार 776 योजनाओं के माध्यम से कुल 91 लाख से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। वर्तमान में 27 लाख 29 हजार ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

- हमारी सरकार आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 21 हजार 448 करोड़ रूपये व्यय कर 7 हजार 920 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण, 979 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, 5 हजार 690 किलोमीटर राज्य राज मार्गों का विकास और 34 हजार 514 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के विकास का कार्य पूर्ण किया गया है।
- समृद्ध किसान–खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ प्रदेश का पहला कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 11 मिशन शुरू किए जा रहे हैं।योजना की राशि को 2 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रूपये किया गया है।
- राज्य के पात्र लघु एवं सीमान्त कृषकों को खरीफ–2022 में संकर मक्का, बाजरा, मूंग, उड़द एवं मौठ के कुल 19 लाख 71 हजार बीज मिनिकिट निःशुल्क वितरित किये गये हैं।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जुलाई, 2022 तक 52 हजार 607 करोड़ रूपए का अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया है।
- राजस्थान का पशुधन के संरक्षण एवं संवर्द्धन में अग्रणी स्थान है। हमारी सरकार ने 300 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्रों के लिए स्वीकृति जारी कर दी है। इन उपकेन्द्रों के लिए 300 पशुधन सहायक तथा 300 जलधारी के नवीन पद भी सृजित किये गये हैं। अब तक 122 नवीन उपकेन्द्र खोले जा चुके हैं। साथ ही 1 हजार 436 पदों पर पशुधन सहायकों की भर्ती शीघ्र ही की जा रही है।
- राज्य पशु 'ऊँट' के संरक्षण तथा समग्र विकास के लिए 'ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति' लागू की है।
- गांवों और ढाणियों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्कूल शिक्षा में अब तक विभिन्न पदों पर 77 हजार 239 नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं तथा 94 हजार 845 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।
- राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा कर सकें, इस ध्येय से वर्तमान में 1 हजार 494 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय संचालित हैं। सभी 33 जिला मुख्यालयों पर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी सत्र 2021–22 से संचालित हैं तथा एक हजार विद्यालयों में इस सत्र से प्रारम्भ की जा रही हैं।
- राज्य में 11 हजार 674 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की जा चुकी हैं। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार 453 बेसिक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशकों की भर्ती की जा रही है।
- मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को राजकीय विद्यालयों में मिड–डे मील की पौष्टिकता में सुधार की दृष्टि से सप्ताह में 2 दिवस (मंगलवार एवं शुक्रवार) दूध उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। योजना में लगभग 500 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है।
- प्रदेश के लाखों कर्मचारी 'न्यू पेंशन स्कीम' के कारण अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। हमारी सरकार ने कर्मचारियों की इस चिंता को समझा और मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए 'ओल्ड पेंशन स्कीम' को पुनः लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस अभूतपूर्व निर्णय से करीब 5 लाख राज्यकर्मियों को भविष्य की अनिश्चितता और आशंका से छुटकारा मिला है और वृद्धावस्था में सम्मानजनक पेंशन प्राप्त करने की गारंटी मिली है।
- इसी प्रकार हमारी सरकार ने विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी–निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारियों तथा पेंशनरों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) शुरू की है। इसके माध्यम से 10 लाख

सेवारत कर्मचारी, 5 लाख पेंशनर एवं उनके परिजन सहित करीब 50 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में बीमित परिवार को 5 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है।
- हमारी सरकार आमजन को त्वरित न्याय, अपराधियों में भय और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
- साइबर अपराधियों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई हेतु प्रत्येक जिले में साइबर थाने खोले जा रहे हैं।पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 834 थानों में स्वागत कक्षों का निर्माण पूरा हो चुका है।
- महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों को दंड दिलाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। दुष्कर्म के प्रकरणों का अनुसंधान तीव्रता से किया जा रहा है। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2022 में अनुसंधान का औसत समय आधा रह गया है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता के लिए चयनित कुल 16 हजार 585 महिला सुरक्षा सखियों द्वारा स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
- खेलों एवं खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अब तक 229 पदक विजेता खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी गई है।
- प्रदेशभर की खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें उचित अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पहली बार 29 अगस्त, 2022 से राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है।
- ओलम्पिक, एशियन एवं राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं, अर्जुन एवं द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाडियों, पैरा खिलाडियों एवं कोच के लिए स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना लागू की है। इन खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह 20 हजार रूपये पेंशन दी जाएगी।
- प्रदेश के अल्प आय वर्ग के युवा दिल्ली में कोचिंग एवं करियर काउंसलिंग लेकर अपना भविष्य संवार सकें, इसके लिए उनके ठहरने की सुविधा हेतु उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रूपए की लागत से 250 कमरों का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एण्ड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है।
- राजस्थान को निवेश फ्रेंडली बनाने एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेकर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है।
- निवेश प्रोत्साहन के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट–2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अब तक 10 लाख 45 हजार करोड़ रूपए के 4 हजार 192 एमओयू एवं एलओआई किये गये हैं। इनमें से 6 हजार 135 करोड़ के निवेश वाले 493 एमओयू एवं एलओआई क्रियान्वित भी हो चुके हैं।
- निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण हेतु 'आई एम शक्ति उडान' योजना आरम्भ कर प्रथम चरण में करीब 29 लाख महिलाओं एवं किशोरियों को लाभान्वित किया गया है। द्वितीय चरण में 1 करोड़ 45 लाख महिलाओं एवं किशोरियों को सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
- हमारी सरकार ने **बैक टू वर्क स्कीम** के तहत प्रशिक्षित प्रोफेशनल एवं कामकाजी महिलाएं, जिन्होंने पारिवारिक अथवा अन्य कारणों से काम छोड़ दिया है, उनको पुनः जॉब के अवसर दिलवाने की व्यवस्था की है।
- हमारी सरकार महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है।करीब 62 हजार आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

- मुख्यमंत्री की पहल पर वर्ष 2020 में जनजातीय जिलों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर तथा सहरिया बहुल जिला बारां में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजनाशुरू की गई थी।द्वितीय चरण में अब यह योजना सभी 33 जिलों में लागू कर दी गई है। योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों के खातों में 6 हजार रूपए की राशि हस्तांतरित की जा रही है।
- प्रदेश के हर नागरिक की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी कटिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में लगभग 94 लाख लाभार्थियों को पेंशन का नियमित भुगतान किया जा रहा है।
- प्रतिभावान विद्यार्थी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की आसानी से तैयारी कर सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारम्भ की गई है।
- कोविड–19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिय मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लागू की गई है। योजना में जून, 2022 तक करीब 139 करोड़ रूपए व्यय कर 209 अनाथ बच्चों, 11 हजार 406 विधवा महिलाओं तथा विधवा महिलाओं के 7 हजार 992 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।
- हमारी सरकार ने आमजन को राहत देने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 प्रारम्भ किया। अभियान के माध्यम से अब तक कुल 4 लाख 3 हजार 806 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। साथ ही अब तक भवन निर्माण अनुज्ञा, नाम हस्तान्तरण, उपविभाजन, पुनर्गठन, लीज से संबंधित कुल 13 लाख 72 हजार 832 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जयपुर के प्रतापनगर में 228 करोड़ रूपए की लागत से प्रदेश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। साथ ही 90 करोड़ रूपए से अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त कॉन्सटीट्यूशन क्लब का निर्माण भी प्रगति पर है।
- शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोरपरिवारों के लिए 'महात्मा गांधी नरेगा योजना' की तर्ज पर इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। इसके लिए 800 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है।
- जरूरतमंद वर्ग को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में 358 स्थायी इन्दिरा रसोई संचालित हैं। वर्ष 2022–23 में रसोइयों की संख्या बढ़ाकर एक हजार करने का लक्ष्य है।
- इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेण्डर्स, बेरोजगार तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को 50 हजार रूपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक **26 हजार** से अधिक शहरी युवाओं को करीब 98 करोड़रूपए का ऋण वितरण किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस नीति, 2019 लागू की गयी है। इससे 9 हजार 718 सिलिकोसिस पीड़ितों एवं परिवारों को करीब 293 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता दी गई है।
- कक्षा 1 से 4 तथा कक्षा 5 से 8 तक के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि क्रमशः 40 से बढ़ाकर 500 एवं 50 से बढ़ाकर 600 रूपये प्रतिमाह की गई है।
- आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत, उपखण्ड एवं जिला स्तर तक जनसुनवाई की प्रभावी व्यवस्था की गई है। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण का संतुष्टि स्तर 91 प्रतिशत से अधिक है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से 11 लाख से अधिक परिवेदनाओं का निस्तारण किया जा चुका है।
- राजस्व संबंधी कार्यों को सुगमता से सम्पादित करने के लिए आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में अब तक ग्रामीण क्षेत्र में 10 लाख 86 हजार पट्टे जारी किये गये हैं। साथ ही

रास्ते संबंधी लगभग 1 लाख 12 हजार प्रकरणों का निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई गई है।

- प्रदेशवासियों को जवाबदेही एवं पारदर्शिता के साथ समय पर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान गारंटीड सर्विसेज डिलीवरी एण्ड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राजकीय विभागों में प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ नियमित भर्तियां सुनिश्चित कर रही है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 1 लाख 29 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है तथा 1 लाख 31 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।परिवहन निगम द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले 1 करोड़ 32 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ दिया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान देश में अग्रणी है। सूचना तकनीक से प्रदेश में बेहतर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है।
- राज्य के स्नातकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए हमारी सरकार जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कर रही है।
- प्रदेश में सर्विस सेक्टर, एमएसएमई एवं स्टार्टअप को सस्ती दर पर प्लग एण्ड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में राजीव गांधी नॉलेज–इनोवेशन हब संस्थान की स्थापना की जाएगी। इन हब्स में महिलाओं के अलग स्थान चिन्हित कर वुमेन हब भी बनाया जाएगा।
- सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं परिवारों की समस्याओं के निराकरण के लिए जयपुर में 20 करोड़ रूपए की लागत से सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा।
- जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2021–22 में 213 करोड़ रूपए की स्वीकृतियां जारी की गई हैं।
- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत 46 हजार 487 व्यक्तिगत एवं 579 सामुदायिक वनाधिकार पत्र जारी किये गये हैं।
- प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। जनजाति क्षेत्र के बालक–बालिकाओं को उच्च स्तरीय हॉकी प्रशिक्षण देने के लिए उदयपुर में हॉकी अकादमी प्रारंभ की गई है।
- राजस्थान के किले, बावड़ी, हवेलियां, ऐतिहासिक धरोहर, पुरा सम्पदा, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला सहित रंग–बिरंगी लोक संस्कृति को देखने देश–विदेश से लाखों पर्यटक खिंचे चले आते हैं।
- राज्य सरकार द्वारा पर्यटन एवं हॉस्पीटेलिटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन इकाइयों पर भी अब उद्योगों के समान टैरिफ और लेवी देय है।
- हमारी सरकार ने **पर्यटन विकास कोष की राशि को 500 करोड़ रूपये से बढ़ाकर** एक हजार करोड़ रूपये किया है। राजस्थान को फिल्म डेस्टीनेशन के रूप में प्रमोट करने तथा राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए **राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति–2022** लागू की गई है।
- राज्य की **ऐतिहासिक 22 बावड़ियों** का **पुनरूद्धार** करने के लिए 19 करोड़ 43 लाख रूपये की योजना स्वीकृत की गई है।
- हमारी सरकार ने 8 लाख 49 हजार निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया है। विभिन्न योजनाओं में 4 लाख 85 हजार श्रमिकों को करीब 927 करोड़ रूपए की राशि से लाभान्वित किया गया है।

- कोविड संकट के दौरान अस्थि विसर्जन के लिए हमारी सरकार ने मोक्ष कलश योजना शुरू की। इस योजना के तहत जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक 42 हजार 658 यात्रियों को हरिद्वार यात्रा कराई गई, जिसके लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 5 करोड़ रूपये का पुनर्भरण किया गया।
- बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व राज्य का चौथा टाईगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है, जिससे बाघों के संरक्षण को मजबूती मिलेगी।
- राज्य में ईको–ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2–2 करोड़ रूपये की लागत से प्रत्येक जिले में लव–कुश वाटिका विकसित की जा रही है।
- राज्य में हरियाली बढ़ाने एवं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2022–23 में करीब 56 हजार 547 हैक्टेयर क्षेत्र में 1 करोड़ 35 लाख पौधे लगाये जा रहे हैं।
- खनिज राजस्व में निरंतर बढ़ोतरी से राज्य के विकास को गति मिली है। वर्ष 2021–22 में खनन गतिविधियों से करीब 6 हजार 395 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ।
- राज्य को खनिज केटेगरी–तृतीयए (अप्रधान खनिज) के प्लॉट आंवटन में वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में उल्लेखनीय कार्य के लिए द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार' प्रदान किया गया।
- देश की प्रथम रिफायनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना का निर्माण तेजी से चल रहा है। विभिन्न कार्यों के लिए जून, 2022 तक 17 हजार 809 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है।
- हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 43 हजार 948 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा है।
- इस वर्ष नहरबंदी के दौरान इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण की मुख्य नहर की कुल 74 किमी में री–लाइनिंग का काम किया गया, जो ऐतिहासिक उपलब्धि है।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में करीब 3 हजार 881 करोड़ रूपये व्यय कर 59 हजार 802 कार्य पूर्ण किये गये हैं। इसी प्रकारइस वित्तीय वर्ष में जून माह तक पंचायतीराज विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 1 हजार 535 करोड़ रूपये व्यय कर 48 हजार 716 कार्य पूर्ण करवाये गये।
- 'महात्मा गांधी नरेगा योजना'में इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 41 लाख 95 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाते हुए करीब 1 हजार 278 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। योजनान्तर्गत टिकाऊ एवं उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जा रहा है।
- पारदर्शिता के लिए समस्त कार्यों को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व, प्रगति के दौरान एवं पूर्ण होने के बाद तीनो स्तरों पर जियो टैगिंग अनिवार्य की गयी है।
- बायोडीजल के उत्पादन, वितरण एंव विक्रय को विनियमित करने के लिए जैव ईधन नियम लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
- राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये एक स्थायी एवं प्रभावशाली त्रि–स्तरीय सामुदायिक संगठन संरचना का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में 32 हजार 494 ग्रामों में लगभग 2 लाख 64 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लगभग 29 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
- मुख्यमंत्री की पहल पर गरीब महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष महिला निधि की स्थापना की जा रही है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 से गौशालाओं को दी जा रही सहायता 180 दिवस से बढ़ाकर 270 दिवस की जा चुकी है। इसके लिए राज्य सरकार 360 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान देगी। इस वर्ष गौशालाओं को लगभग 1 हजार 100 करोड़ रूपये की सहायता दी जाएगी ।
- आगामी वर्ष से जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला, पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम एनजीओ उपलब्ध होंगे, वहां प्राथमिकता से 1–1 करोड़ रूपये से गौशाला स्थापित की जाएगी।
- हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 रूपए प्रति लीटर की दर से देय अनुदान राशि को बढ़ाकर 5 रूपए प्रति लीटर किया है, इसके लिए राज्य बजट में 440 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

भाइयों–बहनों विकास के यह आंकड़े बताते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन, योग्य अधिकारियों एवं कार्मिकों की कर्मठता और जनता जनार्दन के तन–मन–धन से समर्पण के कारण आज हमारा प्रदेश आजादी के 75 वर्ष का गौरवशाली इतिहास रचने में कामयाब हुआ है। प्रदेश का किसान खुशहाल हुआ है, शिक्षा का उजियारा फैला है, स्वास्थ्य का ढांचा सुदृढ़ हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, गांव–ढाणी तक रोशनी फैली है। युवाओं को रोजगार मिला है। समृद्धि और सम्पन्नता बढ़ी है। राजस्थान का हर क्षेत्र में सुनियोजित विकास सुनिश्चित हुआ है।

आइए, इस पावन अवसर पर हम सब संकल्प लें कि जिस त्याग और कठिन संघर्ष से हमें यह आजादी मिली है, उस पर हम कभी आंच नहीं आने देंगे। आपसी भाईचारा और सामाजिक सद्भाव की भावना को और मजबूत बनाते हुए कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बनकर इस देश–प्रदेश की आन–बान–शान को बनाए रखने के लिए हम सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे।

———